RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी.क्र. - MP/KDW/93/2026-28

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

स्मार्ट किसान की पहली पसन्द Haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 5 अंक 04 (मासिक) जून पृष्ठ-8 मूल्य, 5 रुपये

गेहूं खरीदी में एमपी अव्वल, सीएम यादव ने किसानों को दी बधाई

100 लाख मीट्रिक टन की जगह 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में गेहूं खरीदी को लेकर मध्यप्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। नए रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन की जगह 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ है।

मध्यप्रदेश को गेहूं खरीदी के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया।

खाद्य.नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13 लाख 41 हजार 266 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर.1 स्थान हासिल किया है। जबकि,

प्रदेश गेहूं उपार्जन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्नदाताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रहेगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदकर रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश इस मामले में नंबर.1 पर है। इस परिणाम पर सीएम डॉ. मोहन ने खुशी जाहिर की और जनता के लिए संदेश जारी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश के किसानों और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। किसी राज्य ने अगर पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा है, तो वो मध्यप्रदेश है। मध्यप्रदेश ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 करोड़ 4 लाख 31 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गेहूं खरीदी के दौरान किसानों की संख्या सबसे ज्यादा होने में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। और, सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी, तो वो भी मध्यप्रदेश है। लघु किसानों से खरीदी पहले सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्यप्रदेश का दूसरा स्थान है, जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन होने के बाद उसने खरीदी की है। मध्यप्रदेश में पहली बार हमने लघु किसान, मध्यम श्रेणी के किसान का गेहूं खरीदने का निर्णय किया। मुझे बताया गया है कि लगभग पौने चौदह लाख किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया है। जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, उनका गेहूं गोडाउन तक पहुंच चुका है। यह

मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने यह गेहूं खरीदी की है। किसान कल्याण वर्ष में यह परिणाम खास है। हमने 24 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्रेषित की है। हमने किसानों से समर्थन मूल्य 2585 रुपये और 40 रुपये बोनस अर्थात 2625 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा है।

किसानों को हुआ 23,708.13 करोड़ से अधिक का भुगतान

किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 23,708.13 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। उपार्जित गेहूं में से 96 लाख 52 हजार 957 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है। यह उपार्जित गेहूं का 93 प्रतिशत है। किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया है।

मानसून पर अलनीनो का असर, जून में सिर्फ 90 प्रतिशत बारिश का अनुमान

हलधर किसान नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के लिए अपना दूसरा दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई है। इसके साथ ही जून की शुरुआत से ही कई राज्यों में भीषण लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में दीर्घकालिक औसत की 90 प्रतिशत बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें 4 प्रतिशत का उतार-चढ़ाव हो सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार, इस मानसून सीजन में देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा कि यहां सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और मानसून के मुख्य क्षेत्र में इस बार सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

जून के महीने को लेकर डॉ. महापात्र ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत धीमी रहेगी और बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है। हालांकि, उत्तर.पश्चिम भारत, उत्तर.पूर्व भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ चुनिंदा इलाकों में सामान्य बारिश देखी जा सकती है।जून में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान के साथ-साथ रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा।

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि जून के महीने में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में सामान्य से अधिक दिनों तक लू चलेगी। वहीए महाराष्ट्रए तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी लू की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

3765 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को दी बधाई

नई दिल्ली। वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3765.63 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष से 5.3 प्रतिशत अधिक और अब तक का सर्वाधिक स्तर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार की नीतियों का संयुक्त परिणाम बताया है। चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन और गन्ने सहित कई फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान जताया गया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान को मंजूरी देते हुए कहा कि देश का कृषि क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 3765.63 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 3577.32 लाख टन से करीब 188 लाख टन अधिक है। यह अब तक का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देश के अन्नदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और कृषि विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

चावल, गेहूं और मक्का में नई ऊंचाई

फसलवार अनुमान के मुताबिक चावल का उत्पादन 1540.24 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 38.40 लाख टन अधिक है। गेहूं उत्पादन 1206.57 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 550.93 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है।

पोषक एवं मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 744.72 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं श्री अन्न का उत्पादन 175.84 लाख टन तक पहुंच सकता है।

दलहन में चना मजबूत, तूर लगभग स्थिर

दलहन फसलों में चने का उत्पादन 125.14 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से 14 लाख टन अधिक है। तूर का उत्पादन 35.92 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के लगभग बराबर है। मसूर उत्पादन 17.62 लाख टन आंका गया है।

तिलहन और गन्ने में भी शानदार बढ़त

तिलहन उत्पादन 430.59 लाख टन रहने का अनुमान है। मूंगफली का उत्पादन 130.74 लाख टन और रेपसीड- सरसों का उत्पादन 137.68 लाख टन रहने की संभावना है, जो दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर हैं।

सोयाबीन उत्पादन 125.96 लाख टन अनुमानित किया गया है। वहीं गन्ने का उत्पादन 5000.63 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 454.52 लाख टन अधिक है।

तकनीक और बीज सुधार का बड़ा योगदान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके संस्थानों द्वारा विकसित क्लाइमेट.रेज़िलिएंट किस्मों, बारिश आधारित उत्पादन तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह का कृषि उत्पादन बढ़ाने में अहम योगदान रहा है। वर्ष 2025-26 में आईसीएआर ने विभिन्न कृषि.जलवायु क्षेत्रों के लिए 339 नई फसल किस्में जारी कीं। वर्ष 2024.25 में ब्रीडर बीज उत्पादन 109,370.2 क्विंटल और गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन 433,114.7 क्विंटल तक पहुंचा।

मृदा एवं जल संसाधन प्रबंधनए जलवायु-स्मार्ट कृषि, डिजिटल मृदा बुद्धिमत्ता और सतत कृषि तकनीकों ने भी उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कपास और जूट उत्पादन का अनुमान

वाणिज्यिक फसलों में कपास उत्पादन 290.24 लाख गांठ और जूट उत्पादन 91.76 लाख गांठ अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कई प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड स्तर का उत्पादन देश की कृषि क्षमता और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

खरीफ सीजन से पहले पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़े खाद के दाम, किसानों पर पड़ेगी दोहरी मार

हलधर किसान भोपाल।

खरीफ सीजन शुरु होने से पहले किसानों के लिए बुरी खबर है। हाल ही में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से जहां ट्रेक्टर सहित अन्य मशीनरी का उपयोग करने वाले किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा था, इस पर उर्वरक के दाम बढ़ने से जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ है। पहले ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों पर उर्वरक के दाम बढ़ने से दोहरी मार पड़ेगी। हालांकि यूरिया को दामों में कोई बढ़ोत्तरी नही हुई है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते उर्वरकों के दाम बढ़ने लगे हैं, जिसका असर खरीफ सीजन में किसानों पर पड़ेगा। मिट्टी और फसल के पोषण में अहम भूमिका निभाने वाले कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने खरीफ सीजन 2026 के लिए रासायनिक उर्वरकों की नई विक्रय दरें निर्धारित की हैं।

उर्वरक कंपनियों से प्राप्त निविदाओं के आधार पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ने खरीफ सीजन 2026 के लिए रासायनिक उर्वरकों की बिक्री दरें निर्धारित की हैं। अब पूरे सीजन के दौरान किसानों को इन्हीं दरों पर रासायनिक उर्वरकों की बिक्री होगी। इनमें यूरिया शामिल नहीं है, क्योंकि यूरिया की ब्रिी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है और उसके दाम अभी नहीं बढ़े हैं।

इसी तरह विनियंत्रित उर्वरक डाईअमोनियम फॉस्फेट ;डीएपीद्ध की कीमत भी 1350 रुपये प्रति 50 किग्रा बैग पर स्थिर रखी गई है। इसके लिए सरकार अतिरिक्त सब्सिडी दे रही हैए जिससे इस साल सब्सिडी का बोझ बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण उर्वरकों और गैस के आयात में बाधाएं आ रही हैं, जिससे उर्वरक उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उर्वरक कंपनियों ने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने एनपीके 16-16-16 का दाम 2050 रुपये प्रति बैग तय किया गया है, जो पिछले साल 1475 रुपये था। अमोनियम सल्फेट का दाम 1400 रुपये प्रति बैग रखा गया है, जो पिछले साल 950 रुपये था। इसी तरह एमओपी (पोटाश) का 50 किग्रा बैग अब 1975 रुपये में मिलेगा, जबकि पिछले साल इसका रेट 1535 रुपये था। सिंगल सुपर फॉस्फेट (दानेदार) का रेट 605 रुपये प्रति बैग तय किया गया है, जो पिछले खरीफसीजन में 505 रुपये प्रति बैग था। उर्वरकों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी का असर खेती की लागत और किसानों की आय पर पड़ेगा।

क्या है नई दरें

नई दरों के अनुसार, एनपीके ;12-32-16 और एनपीके 10-26-26 का 50 किलोग्राम का बैग अब 2450 रुपये में मिलेगा, जबकि पिछले खरीफ सीजन में इनकी कीमत 1720 रुपये थी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा एनपीके (20-20-0-13) का रेट अभी तय नहीं किया जा सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस एनपीके वेरिएंट के लिए उर्वरक कंपनियों ने 2100 रुपये प्रति बैग की दर की पेशकश की है, जिसे कम करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उर्वरक उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अमोनिया, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की कमी के चलते एनपीके उर्वरकों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। देश में सालाना करीब 400 लाख टन यूरिया, करीब 100 लाख टन डीएपी और करीब 140 लाख टन कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की खपत होती है। इस समय सरकार का जोर यूरिया और डीएपी की उपलब्धता बढ़ाने पर है और इसके लिए एलएनजी तथा तैयार उर्वरकों की खरीद पर ध्यान दिया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों में भी उर्वरकों के दाम कमोबेश इतने ही रहेंगे।

इस बीच, सरकार उर्वरकों की खपत कम करने के प्रयास भी कर रही है। इसके लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया था।

सरकार का दावा, देश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक

नई दिल्ली। खरीफ 2026 सीजन की तैयारियों के बीच देश में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर उठ रही चिंताओं पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि भारत की उर्वरक सुरक्षा फिलहाल मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है। किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय के अनुसार, आगामी खरीफ 2026 सीजन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कुल उर्वरक आवश्यकता 390.54 लाख मीट्रिक टन आंकी है। इसके मुकाबले वर्तमान में देश में करीब 200.12 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है, जो अनुमानित आवश्यकता का लगभग 51 प्रतिशत है। हालांकि सरकार ने उपलब्धता को संतोषजनक बताया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से शिपिंग गतिविधियों में आई सीमाओं के कारण भविष्य की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बुवाई के चरम समय और उसके बाद की मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत उर्वरकों के आयात पर काफी हद तक निर्भर करता है। उर्वरक विभाग ने कहा कि हालिया वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू उत्पादन और आयात के माध्यम से लगभग 117.6 लाख टन अतिरिक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सबसे अधिक उत्पादन यूरिया का रहा। देश में 57.66 लाख टन यूरिया का घरेलू उत्पादन हुआ, जबकि 13.60 लाख टन यूरिया आयात कर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचाया गया। डीएपी (डाय.अमोनियम फॉस्फेट) का घरेलू उत्पादन 7.93 लाख टन रहा और 0.88 लाख टन का आयात किया गया। इसी तरह एनपीके उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 18.71 लाख टन दर्ज किया गया, जबकि 4.44 लाख टन आयात हुआ। एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) का उत्पादन 10.70 लाख टन रहा और इसका कोई आयात नहीं किया गया।

वहीं एमओपी म्यूरिएट ऑफपोटाश का घरेलू उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन 3.68 लाख टन आयात किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल घरेलू उत्पादन 95 लाख टन रहा, जबकि 22.60 लाख टन उर्वरक विभिन्न बंदरगाहों पर आयात के जरिए पहुंचे।

जेब के लिए बुरी खबर हैः 42 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थोक मुद्रास्फीति

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के भंडार में भारी उथल-पुथल के कारण, भारत में थोक स्टॉक (डब्ल्यूपीआई) में भारी उछाल आया है। वर्तमान में थोक स्टॉक 8.30 प्रतिशत तक पहुंच गई है? यह मार्च के 3.88 प्रतिशत से अधिक है और पिछले 42 महीनों का सर्वोत्तम स्तर है।

पिछले साल अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

मुद्रास्फीति 0.85 प्रतिशत थी।

डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार, ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति मार्च में 1.05 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 24.71% हो गई, जो थोक मुद्रास्फीति में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरी है।

कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में क्रमिक रूप से 16.42% की वृद्धि हुई। अप्रैल में इस श्रेणी में मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 67.18% तक पहुंच गई, जिसमें अकेले कच्चे पेट्रोलियम की मुद्रास्फीति 88.06% तक बढ़ गई।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज के अनुसार, विश्व सूचकांक मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि इस श्रृंखला में अब तक की सबसे अधिक रही है।

लेकिन क्या वर्किंग वैल्यू इंसेंटिव में वृद्धि वास्तव में उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगी ?

विश्व स्वास्थ्य संस्थान का घरेलू खर्चों से क्या संबंध है?

यह देखते हुए कि विश्व सूचकांक मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) घरेलू खर्चों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती है, डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा उच्च डब्ल्यूपीआई अक्सर उच्च सीपीआई में तब्दील नहीं होता है, खासकर व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं या बाहरी झटकों के दौर मेंय इन दोनों चरों के बीच सहसंबंध काफी कमजोर है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों सूचकांक अलग.अलग चीजों को मापते हैं . सीपीआई मुख्य रूप से खाद्य और सेवाओं की कीमतों से प्रभावित होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई विनिर्माण और ईंधन की लागत से अधिक प्रभावित होता है, और मध्य.पूर्व संकट के बाद इन दोनों में वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, लागत का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ने में आमतौर पर कुछ समय लगता है। ईंधन कर में कटौती और सब्सिडी जैसे सरकारी उपायों से खुदरा मुद्रास्फीति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। अप्रैल 2026 के आंकड़ों में अंतर इसी वजह से देखने को मिला, जब विश्व सूचकांक मुद्रास्फीति तेजी से बढ़कर 8.3% हो गई, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम यानी 3.48% रही।

इससे किन लोगों के प्रभावित होने की संभावना है?

आयातित मुद्रास्फीति से विश्व सूचकांक मुद्रास्फीति में जल्द ही वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका कारण कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की मुद्रास्फीति 67.2% की वृद्धिद्ध और ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 24.7% की वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा अवमूल्यन है।

रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे आयातित कच्चे माल पर निर्भर कंपनियों को मार्जिन के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इनपुट लागत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। मजूमदार ने बताया।

हाल ही में थोक मुद्रास्फीति में आई तेजी के बावजूद, आरबीआई द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की उम्मीद है, क्योंकि अप्रैल 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.48% पर आरबीआई के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है..मजूमदार ने कहा।

हालांकि, आयातित मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, भू.राजनीतिक तनाव, रुपये के अवमूल्यन और मौसम संबंधी खाद्य मुद्रास्फीति के संभावित जोखिमों के बारे में चिंताओं के कारण वर्ष के अंत में ब्याज दरों में वृद्धि के एक संभावित चक्र की उम्मीदें बढ़ रही हैं।

क्रिसिल की क्विकोनॉमिक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित इनपुट.आउटपुट अनुपात अप्रैल 2026 में लगभग चार वर्षों बाद 1.0 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। यह अनुपात लगातार 44 महीनों तक 1.0 से नीचे रहने के बाद 1.02 पर पहुंच गया। यह संकेत है कि अब उत्पादन लागत, तैयार उत्पादों की कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, इनपुट कीमतों में महीने.दर.महीने 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आउटपुट कीमतों में केवल 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, इस्पात, उर्वरक, प्लास्टिक, रसायन, सिंथेटिक रबर और गैर.लौह धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी लागत वृद्धि के प्रमुख कारण रहे। इससे पहले मार्च 2022 में रूस.यूक्रेन संघर्ष के बाद इनपुट.आउटपुट अनुपात 1.0 से ऊपर गया था और तब यह स्थिति करीब पांच महीनों तक बनी रही थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2026 में कुल थोक महंगाई औसतन केवल 0.7 प्रतिशत रही, लेकिन प्रमुख औद्योगिक इनपुट की कीमतों में पहले से ही तेजी देखी जा रही थी। पिछले वित्त वर्ष में तांबे की कीमतों में औसतन 8.7 प्रतिशत और एल्युमीनियम में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इनके दीर्घकालिक औसत से अधिक है।

महंगाई का दबाव अप्रैल 2026 से ही दिखने लगा है। थोक महंगाई मार्च के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर पिछले महीने 8.3 प्रतिशत हो गई, जबकि गैर.खाद्य महंगाई (थोक) 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 10.9 प्रतिशत पहुंच गई। इसी दौरान तांबे की कीमतों में 17.3 प्रतिशतए एल्युमीनियम में 20.6 प्रतिशत, कच्चे तेल आधारित उत्पादों में 49.3 प्रतिशत और गैस आधारित उत्पादों में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। क्रिसिल ने चेतावनी दी कि भले ही होर्मुज जलडमरूमध्य दोबारा खुल जाए, लेकिन वैश्विक आपूर्ति व्यवधान और कमोडिटी कीमतों पर लगातार दबाव के कारण इनपुट लागत कुछ समय तक ऊंची बनी रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू मांग मजबूत रहने के कारण कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विशेष रूप से कोर महंगाई पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए क्रिसिल की प्रधान अर्थशास्त्री दीप्ति देशपांडे ने कहा, लगातार 44 महीनों तक 1.0 से नीचे रहने के बाद इनपुट.आउटपुट अनुपात का इस स्तर को पार करना लागत के बढ़ते दबाव का संकेत है। ऊर्जा और अन्य इनपुट लागत में तेज वृद्धि का सामना कर रहे उत्पादकों के कारण आने वाले महीनों में कोर खुदरा महंगाई बढ़ने की आशंका है।

वर्तमान में हम वित्त वर्ष 2027 में औसत खुदरा महंगाई 5.1% रहने का अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर जाने का जोखिम है, क्योंकि आने वाले समय में उद्योग बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर डालेंगे। सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान और संभावित अल नीनो परिस्थितियों के बीच यदि मानसून में कोई बड़ी बाधा आती है, तो खाद्य महंगाई पर नया दबाव बन सकता है।

बैंक शाखा में 41.58 लाख रुपए का गबन, कैशियर, सहायक गणन के बाद शाखा प्रबंधक पर गिरी निलंबन की गाज

हलधर किसान खरगोन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध ठीबगांव शाखा में 41.58 लाख रुपये का गबन उजागर होने के बाद बैंक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आनन-फानन में कार्रवाई कर राशि रिकवरी के प्रयास किए जा रहे है। बैंक एमडी ने ठीबगांव शाखा कैशियर, सहायक गणक सहित शाखा प्रबंधक के बैंक खाते सीज करा दिए है। इसके अलावा तीनों पर एफआईआर की कार्रवाई के लिए शिकायती आवेदन भी जैतापुर पुलिस थाने पर दिया है। जैतापुर थाना प्रभारी के अनुसार शिकायती आवेदन पर एफआईआर की जा रही है। विभागीय स्तर पर भोपाल से भी जांच दल गठित किया गया है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीईओ संध्या रोकड़े ने बताया कि 25 मई 2026 को शाखा में नियमित नगद मिलान एवं भौतिक सत्यापन के दौरान कैश का गबन सामने आया। जांच में बैंक की वास्तविक नगद शेष राशि और अभिलेखों में दर्ज राशि में 41लाख 58 हजार 95 रुपए का अंतर पाया गया। दोपहर बाद कैशियर रितु गोयल बिना किसी पूर्व सूचना के शाखा से अनुपस्थित हो गई थीं तथा उनके मोबाइल फोन भी बंद पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर शाखा में पंचनामा तैयार किया गया। मामले की सूचना पुलिस थाना जैतापुर को भी दी गई। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि शाखा स्तर पर नकद हस्तांतरण एवं संयुक्त निरीक्षण संबंधी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कैशियर रितु गोयल, सहायक गणक वाल टेलर त्रयम्बक वाणी के साथ ही शाखा प्रबंधक राजेश राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीईओ ने ग्राहको को आश्वस्त किया है कि बैंक की राशि को किसी तरह का नुकसान नही होगा। राशि रिकवरी के लिए तीनों दोषी कर्मचारियों के बैंक खाते सीज कर दिए है। जल्द ही यह राशि इनके बैंक खातों से रिकवर की जाएगी। विभागीय दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है।

मार्च से ही मिला था कॅशियर का चार्ज

बैंक से मिली जानकारी अनुसार कैशियर रितू गोयल को मार्च में ही चार्ज दिया गया था। इससे पहले इसी शाखा में बाबू के पद पर कार्यरत थी। यहां पदस्थ कैशियर के सेवानिवृत्त होने के बाद रितू को कैशियर का चार्ज दिया गया था। संभवतः लाखों का लेन-देन होने पर नियत डोल गई और अमानत में खयानत कर बैठे।

केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस के लिए 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेगी

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 16वें वित्त आयोग की आबंटन अवधि में राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता . सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय (सार्थक पीडीएस) योजना को एक व्यापक योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जा रहा है।

सीसीईए ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों की अंतरराज्यीय आवाजाही और हैंडलिंग तथा एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के मानदंडों को संशोधित करने और केंद्रीय सहायता के मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न को जारी रखने का भी निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने 27 मई को अपने सार्वजनिक खाद्य वितरण नेटवर्क में 25,530 करोड़ रुपये के सुधार को मंजूरी दी, जिसमें दो मौजूदा सब्सिडी कार्यक्रमों को एक ही प्रौद्योगिकी.आधारित योजना में विलय कर दिया गया है, जिसे 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अधिक कुशलतापूर्वक और कम बर्बादी के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वित्त वर्ष 2027 से शुरू होने वाली पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य परिवहन सब्सिडी और उचित मूल्य दुकान कमीशन को सार्थक.पीडीएस नामक एक ही कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगाए साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि सरकार को खाद्यान्न परिवहन मार्गों के युक्तिकरण से प्रतिवर्ष 280 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्याणकारी सेवाओं के वितरण को डिजिटाइज़ करने के प्रयासों को दर्शाती हैए जो एक दशक से किए जा रहे सुधारों पर आधारित है, जिसके तहत राशन कार्ड को आधार डेटाबेस से जोड़ा गया है और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित किया गया है।

वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि नई एकीकृत योजना का उद्देश्य वास्तविक समय की निगरानी, शिकायत निवारण, विश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों को तैनात करके एक एकीकृत, नागरिक.केंद्रित वास्तुकला का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली खाद्य सुरक्षा आयोग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सार्थक.पीडीएस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा ढांचे का समर्थन करेगा, जिससे खाद्यान्न की अंतिम मील तक डिलीवरी सुनिश्चित होगी, लीकेज कम होगा और सिस्टम में पारदर्शिता में सुधार होगा।

इस योजना में मानकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर, एकीकृत डेटाबेस, राज्य स्तरीय कमांड और नियंत्रण केंद्र और आईएसओ.प्रमाणित परिचालन ढांचे का भी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की सुरक्षाए पारदर्शिता और स्थिरता में सुधार करना है।

यह एकीकृत योजना पिछले दशक में किए गए डिजिटलीकरण सुधारों पर आधारित है, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन और स्मार्ट पीडीएस पहल शामिल हैं।

अप्रैल 2023 से, स्मार्ट पीडीएस कार्यक्रम ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई.पीओएस उपकरणों, ऑनलाइन आवंटन प्रणालियों और कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति.श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन को सक्षम बनाया है।अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं को एक ही व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत करने से कार्यान्वयन में सुगमता आएगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा और रियायती अनाज वितरण के लिए अधिक प्रौद्योगिकी.आधारित तंत्र उपलब्ध होगा। प्रस्तावित परिवर्तनों से अनाज परिवहन को सुव्यवस्थित करके कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की भी उम्मीद है।

प्रधानमंत्री को रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से एग्रीकोला मेडल से किया सम्मानित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री ने एफएओ के महानिदेशक डॉ. क्यू डोंग्यू से यह पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने यह सम्मान भारतीय किसानों और भारतीय कृषि वैज्ञानिक समुदाय को समर्पित किया, जो भारतीय लोगों के साथ-साथ विश्व भर के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उन्होंने बताया कि यह सम्मान मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के प्रति भारत की दृढ़ता के प्रति आदर को दर्शाता है। भारत में किसानों के जीवन के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि धरती माता और भारतीय जनता के बीच एक पवित्र बंधन है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक और नवाचार आधारित कृषि का दृष्टिकोण एक टिकाऊ, जलवायु-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। इस दिशा मेंए उन्होंने बताया कि श्हर बूंद से अधिक फसल जैसी पद्धतियां और सूक्ष्म सिंचाई एवं सटीक खेती के लिए मिशन-आधारित दृष्टिकोण भारत की कृषि नीतियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी आधारित कृषि समाधानों पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई.आधारित चेतावनी प्रणालियां, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग तकनीक और सेंसर-आधारित मशीनरी भारतीय किसानों को भरपूर फसल और अधिक आय प्राप्त करने में मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, भारत ने लगभग 3,000 जलवायु.अनुकूल फसल की किस्में विकसित की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विज्ञान.आधारित कृषि विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि एफएओ के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और भुखमरी से मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए संगठन के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उत्सव के माध्यम से स्वस्थ भोजन के विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु भारत के साथ काम करने के लिए एफएओ को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का एफएओ मुख्यालय का दौरा पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा है।

गृहमंत्री शाह से मिला एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन कृषि व्यापार और किसानों की समस्याओं का सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली।

ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री के नेतृत्व के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता अमित शाह से उनके निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने देश के 12 लाख कृषि इनपुट डीलरों और करोड़ों किसानों के हितों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चार महत्वपूर्ण मांग पत्र गृहमंत्री को सौंपा।

इस प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण पटेल, संगठन मंत्री सुभाष शाह, संगठन मंत्री अरविंद पटेल और सदस्य रमेश पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थे।

यह है मांगें-

मध्यप्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रदेश पदाधिकारी विनोद जैन एवं खरगोन जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चावला ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन ने गृहमंत्री को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि- किसी कंपनी द्वारा सीलबंद पैकेट या बोतल का सरकारी सैंपल फेल होता है, तो दवा विक्रेताओं (फार्मास्युटिकल) के कानून की तर्ज पर इसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। मूल सीलबंद अवस्था में माल बेचने वाले डीलरों को निर्दोष माना जाए।

-'उर्वरक मार्जिन में बढ़ोतरी और टैगिंग पर लगे रोक

वर्ष 1995 से स्थिर 24 प्रति बैग के डीलर मार्जिन को आज की बढ़ी हुई एमआरपी के अनुसार होलसेलर और रिटेलर दोनों के लिए मिलाकर कुल 8 प्रतिशत तय किया जाए। इसके अलावा, खाद निर्माता कंपनियों द्वारा यूरिया और डीएपी के साथ गैर.अनुदानित उत्पादों को जबरन बेचने (टैगिंग) की प्रथा पर तुरंत रोक लगाई जाए।

-कीटनाशकों पर जीएसटी की दरें कम करना

किसानों की खेती की लागत को कम करने के लिए कीटनाशकों पर वर्तमान 18 प्रतिशत जीएसटी की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई, जिससे देश के अन्नदाताओं को लगभग 4,550 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मिलेगी।

-जटिल टीडीएस प्रावधान और डेटा विशिष्टता का विरोध

आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393(1) पुरानी धारा 194एफ, के तहत व्यापारियों पर लादे गए जटिल टीडीएस नियमों को समाप्त करने की मांग की गई। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेटेंट अवधि समाप्त होने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार बढ़ाने के प्रयासों को रोकने का अनुरोध किया गया, ताकि घरेलू एग्रोकेमिकल उद्योग और किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

गृह मंत्री ने दिया आश्वासन

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को बेहद सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से इन सभी व्यावहारिक समस्याओं का उचित और सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा।

मतस्य विभाग ने रात्रि लगाई मछुआ चौपाल, ग्राम देजला में मत्स्यपालकों को दी योजनाओं की जानकारी

केज कल्चर से आयवर्धन एवं बीमा सुरक्षा पर दिया गया मार्गदर्शन

हलधर किसान खरगोन

कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशन में मत्स्य विभाग ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत ग्राम देजला में समृद्ध किसान की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से 27 मई को रात्रि मछुआ चौपाल का आयोजन किया गया।

चौपाल में विभागीय योजनाओं तथा मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत केज कल्चर स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रण की विस्तृत जानकारी आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति देजला-देवाड़ा के सदस्यों एवं अन्य मत्स्य पालकों को प्रदान की गई।

मछुआ चौपाल में खारक बांध समिति के सदस्य, ग्राम भग्यापुर, करही एवं भगवानपुरा के मत्स्य पालक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर बताया गया कि मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत केज कल्चर आधुनिक एवं स्मार्ट मत्स्य पालन तकनीक है, जिससे सीमित निवेश में बेहतर आय, जलाशयों का पूर्ण उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, उच्च गुणवत्ता की मछलियों का उत्पादन तथा पोषणयुक्त आहार की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। साथ ही केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालकों के लिए आय के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

जिले के पाँच बड़े जलाशयों- देजला-देवाड़ा, खारक, अपरवेदाख सतसोई एवं साटक में हितग्राही मॉडल अंतर्गत केज स्थापना के लिए संचालनालय मत्स्योद्योग, मप्र भोपाल द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन की अंतिम तिथि 07 जून तक हैं।

इस अवसर पर मत्स्य निरीक्षक गोपाल पाटीदार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की जानकारी देते हुए जलकृषि बीमा के लाभों पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत सुरक्षित उत्पादन एवं सुरक्षित आय सुनिश्चित की जाती है। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसान ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, प्रीमियम पर 40 प्रतिशत एकमुश्त प्रोत्साहन सहायता, अधिकतम 1 लाख तक सहायता तथा रोग, प्रदूषण, जैविक जोखिम, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती है। सहायता राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। जिले के सभी मत्स्य पालकों से योजना का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग रमेश मौर्य ने बताया कि मछुआ चौपाल का उद्देश्य मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 की विस्तृत जानकारी देनाए मछुआरों को योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराना तथा मत्स्य पालन से जुड़ी समस्याओं एवं कठिनाइयों का समाधान करना है। कलेक्टर के निर्देश पर इसे एक नई पहल के रूप में ग्राम पंचायत देजला में आयोजित किया गया।

मछुआ चौपाल में मत्स्य निरीक्षक जतनसिंह रावत, जयंतीलाल पाटीदार, सरपंच देवाड़ा कैलाश ब्राम्हणे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

औपचारिकता भर न रह जाए विश्व पर्यावरण दिवस

एक बार फिर पांच जून आ पहुंचा है। यानी वह दिन जब हम श्विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पर बड़ी श्रद्धा से एक बार फिर सारी घिसी-पिटी औपचारिकताएं निभाएंगे। कोई बरगद का बोंजाई गमले में लगाएगा, तो कोई नौतपा में पीपल, जामुन, आम के पौधे लगाएगा, कोई हरे.भरे गमले थामे हुए सेल्फी खिंचवाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की दीवारें ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ..जैसे नारों से पट जाएंगी। अधिकारीगण भाषण देंगे, कुछ भाषण सुनने की रस्म निभाएंगे और अगले दिन सब अपने-अपने निर्धारित एजेंडे पर लौट जाएंगे। यानी पर्यावरण.विनाश की एकसूत्रीय योजना में पुनः सक्रिय हो जाएंगे। दरअसल, हमने कभी पर्यावरण की चिंता की ही नहीं। हमारा विकास मॉडल ही ऐसा है, जिसमें प्रकृति के लिए कोई स्थान ही नहीं। विज्ञान से हमने क्या सीखा? यही कि हर प्रगति अब प्रकृति पर एक और प्रहार है। हमने विज्ञान को विकास का औजार तो बना लिया, पर विवेक को कूड़ेदान में डाल दिया। परिणाम यह कि विकास और पर्यावरण अब एक वाक्य में दो तलवारों की तरह हो गए हैं-जो एक म्यान में साथ रह ही नहीं सकते। आज जलवायु परिवर्तन केवल एक वैश्विक बहस नहीं, हमारे फेफड़ों में घुला जहर बन चुका है। कहीं तापमान 50 डिग्री पार कर गया है, तो कहीं बर्फबारी जून में हो रही है। लगता है, पृथ्वी अपने संतुलन को खो चुकी है। कभी आग बरसाती गर्मी, तो कभी आइस एज की आहट। भारत में इस वर्ष मई में देश के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया, जो भारत में अब तक का सर्वाधिक तापमान बन गया। बादल अब मौसम विभाग की परिभाषाओं को ठेंगा दिखाते हैं। न कैलेंडर में दर्ज ऋतुएं समय पर आती हैं, न पंचांगों के ग्रह नक्षत्र अब वर्षा का अनुमान दे पाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले 50 वर्षों में मानसून की स्थिरता 27 प्रतिशत तक घट गई है। प्रतीक्षित वर्षा और वास्तविक वर्षा के बीच का अंतर अब औसतन 19 प्रतिशत हो गया है। पर हमारे विकास मॉडल को देखिए- वह सस्टेनेबिलिटी से कोसों दूर भागता है। अब पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हम बड़े गर्व से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं। मानो बिजली से चलने वाला वाहन अपने आप में समस्त पर्यावरण पापों को विनष्ट करने वाला पावन गंगा जल हो गया हो! परन्तु क्या कभी हमने आत्मा से पूछ कर देखा है कि उस बैटरी के निर्माण और निष्पादन की प्रक्रिया कितनी विषैली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 2022.23 में लगभग 70,000 टन लिथियम.आयन बैटरियाँ आयात हुईं, जिनमें से 95 प्रतिशत का कोई पर्यावरण.सुरक्षित रीसायक्लिंग सिस्टम नहीं है। उनकी रीसायक्लिंग की प्रक्रिया या तो अस्तित्व में नहीं है या बेहद सीमित है। दूसरा सवाल- वह बिजली कहां से आ रही है, जिससे ये पर्यावरण हितैषी का ठप्पा माथे पर चिपकाए हमारी ये ईवी चार्ज होते हैं? क्या कोयले से बिजली बनाना प्रदूषण मुक्त प्रक्रिया है? भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 72 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आज भी थर्मल पावर प्लांट्स का है। इनमें से अधिकांश कोयले से चलने वाले हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश का प्रमुख स्त्रोत हैं। जिस सौर ऊर्जा को हम पवित्र गाय मान बैठे हैं, क्या उसकी सोलर प्लेट्स को हम 100 प्रतिशत रीसायकल कर सकते हैं? फ्रेंच एनवायर्नमेंटल एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सोलर पैनल का केवल 10.15 प्रतिशत ही प्रभावी रूप से रीसायकल हो रहा है। भारत में यह प्रतिशत और भी कम है। आज खेतों में करोड़ों टन रासायनिक खाद डाली जा रही है, जिसकी गैसें जल, थल, नभ तीनों को बर्बाद कर रही हैं। कीटनाशकों से न केवल मिट्टी मर रही है, बल्कि वह मृत्युभोज धीरे-धीरे हमारे शरीर में पहुँच रहा है।

ज्योतिष हो या विज्ञान, मानसून पर सबकी राय एक समान

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन(सोनी) अजमेर

ज्योतिष गणना से जानिए कैसा रहने वाला है मानसून

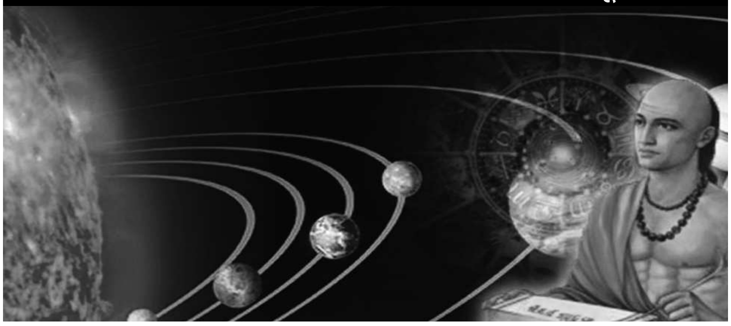

अजमेर। सुपर अल नीनो के प्रभाव से जहां मौसम विज्ञानी इस बार सामान्य से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान लगा रहे हैं, वहीं ज्योतिषाचार्यों ने भी नव विक्रम संवत्सर में ग्रहमंडलीय स्थिति के कारण ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। अब ऐसे ही लक्षण नौतपा के मध्य भी बनने की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप सोनी (जैन) के अनुसार आधुनिक मौसम विज्ञान हालांकि ज्योतिषीय कालखंड नौतपा को सीधे-सीधे नहीं मानता, लेकिन इन्हीं नौ दिनों के कालखंड में प्री-मानसूनी परिस्थितियां बनने की संभावना वर्षा संबंधी भविष्यवाणी को सत्य होने की पटकथा लिखती दिखाई देती हैं।

क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यदि नौतपा के बीच में तापमान घटा और वर्षा हुई तो इससे मानसून कमजोर होगा। उधर विज्ञान भी प्रबल मानसून के लिए मई माह की प्रचंड तपन को आवश्यक मानता है।

मध्य से लेकर उत्तर भारत तक इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 44 से 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। अभी नौतपा का तपना शेष है। ज्योतिष सोनी के अनुसार सूर्यदेव जब आर्द्रा से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर वृष राशि के 11 से 19 अंश तक रहते हैं तब नौतपा होता है। यह स्थिति इस बार 26 मई से तीन जून तक बन रही है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार नौतपा के दिनों में तपन जितनी अधिक होती है, आने वाले समय में मानसून उतना ही बेहतर होता। भारतीय ज्योतिष नौतपा को मानसून का गर्भकाल मानती है।

यानी नौतपा के बीच में वर्षा मानसून को कमजोर करेगी। मौसम विज्ञान का अलनीनो को लेकर कम वर्षा का पूर्वानुमान, ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों-नक्षत्रों की स्थिति और नौतपा के बीच में बादल-बूंदाबांदी सभी का समवेत निष्कर्ष सामान्य से कम वर्षा का संकेतक है।

ज्योतिष सोनी बताते हैं कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मान्यता है कि सूर्य की गर्मी और रोहिणी नक्षत्र के कारण चंद्रमा का जल तत्व मानसून के गर्भ में आ जाता है। यह काल नौ दिनों का होता है। इस समय चंद्रमा नौ नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। लोक मान्यता है कि अगर नौतपा के सभी नौ दिन पूरे तपे, तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है। चंद्रमा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपनी स्थितियों में हो और अधिक गर्मी पड़ेए तो वह नौतपा अच्छा कहलाता है। वहीं अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है और उस दौरान यदि वर्षा हो जाती है तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना (गर्भपात) भी कहा जाता है। मानसून को ग्रहों.नक्षत्रों से परे विशुद्ध मौसम का चक्र है। गर्मी में नक्षत्र की भूमिका रहती तो मकर रेखा में स्थित देशों में इस समय दिन का तापमान कम क्यों रहता। इस समय आस्ट्रेलिया में दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, मालदीव में 32 डिग्री के आसपास है। रोहिणी नक्षत्र पृथ्वी से 65 प्रकाश वर्ष दूर है, वह केवल किसी एक-दो देश के तापमान बढ़ाने का काम क्यों करेगा। सूरज का रोहिणी में आना केवल उस समय को एक घड़ी की तरह बताता है, जब मध्य भारत में गर्मी पड़ती है। इसलिए रोहिणी को समझें घड़ी का कांटा, पूरे पृथ्वी से गर्मी से नहीं है इसका नाता।

रोहिणी में वर्षा, मानसून का गर्भपात

वर्ग पहेली नं. 23 बाएं से दाएं

1. कश्ती, नौका (2)
3. भारत का राष्ट्रीय पुष्प (3)
6. गुल्फ, पिंडली और एड़ी के बीच की हड्डी (3)
7. गायकों के साथ संगत करने वाला एक तारवाद्य (2)
9. गदहा, गर्दभ (2)
10. तरफदारी, दो पक्षों में एक का पक्ष लेना (4)
12. पक्षी, आकाश में विचरण करने वाला (4)
13. राष्ट्र का पहला नागरिक (4)
14. दासी, सेविका, भृत्या (4)
16. स्याही (2)
17. जैन धर्म के एक तीर्थंकर (4)
19. गवाक्ष, झरोखा (3)
20. लाठी (3)
21. अगर (2)

ऊपर से नीचे.

2. भारत का राष्ट्रीय पेड़ (4)
3. श्राद्ध (4)
4. बेल (2)
5. जिसका कोई सहारा या आधार न हो (4)
8. मनुष्यों को खाने वाला, राक्षस (5)
11. सबक देना, शिक्षा देना (5)
13. राजगद्दी, शासन (4)
14. हाल में काम सीखने वाला (4)
15. शासकीय (4)
18. जमीन, स्थल (4)

१	२	■	३		४	■	■	५
■	६			■	७	८		
■		■	९		■		■	
१०		११		■	१२			
■	■		■	■	■		■	■
१३				■	१४		१५	
	■		■	१६		■		■
१७			१८	■	१९			■
	■	■	२०			■	२१	

वर्ग पहेली नंबर 22 का हल

१ गं	२ गा	■	३ अ	घो	४ री	■	■	५ स
■	६ ली	च	ड़	■	७ ति	८ क	ड़	म
■	दे	■	९ च	स्का	■	था	■	झौ
१० ट	ना	११ ट	न	■	१२ वि	वा	ह्रि	ता
■	■	क	■	■	■	च	■	■
१३ अ	प	रा	ध	■	१४ च	क	१५ रा	ना
नु	■	ह	■	१६ चो	ट	■	स	■
१७ प	ल	ट	१८ ना	■	१९ प	स	ली	■
म	■	■	२० प	ल	टा	■	२१ ला	भ

नकली बीज-खाद की मार से कब उबरेंगे किसान ?

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय खरीफ2026 की तैयारियों में जुटा है। इस बार 15 से 20 फीसदी अधिक उत्पादन का लक्ष्य है। दूसरी ओर, किसान इस चिंता में हैं कि उन्हें उचित कीमत पर असली उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक मिल पाएंगे या नहीं! मिलावटी कृषि इनपुट की समस्या हर साल गंभीर होती जा रही है, लेकिन इस पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार इस मुद्दे को खुलकर गंभीर बताया और किसानों को न्याय दिलाने की बात कही है, हालांकि अभी तक कोई सख्त कानून लागू नहीं हो सका है। पिछले खरीफसीजन से पहले विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान देश भर के गांवों में किसानों ने नकली बीज व खाद, घटिया कीटनाशक और नैनो यूरिया की जबरन बिक्री जैसी समस्याएं उठाईं। इन शिकायतों के बाद मंत्रालय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक कदम उठाने शुरू किए थे।

मजबूत करनी होगी खेती की बुनियाद

बीज खेती की बुनियाद हैं और इस क्षेत्र में कई कंपनियां सक्रिय हैं, लेकिन बाजार में नकली और घटिया बीजों की समस्या लगातार बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में जांचे गए 8,09,033 नमूनों में से 3,33,532 नमूने निम्न गुणवत्ता के पाए गएए जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सरकार ने संसद में भी इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है। हालांकि, बीज विधेयक 2025 अभी तक संसद में पेश नहीं हो सका है।

प्रस्तावित विधेयक में फर्जी कंपनियों पर रोक के लिए अनिवार्य पंजीकरण, घटिया बीज बेचने वालों पर 30 लाख रुपये तक जुर्माना व सजा और दावे के अनुरूप प्रदर्शन न होने पर किसानों को मुआवजे का प्रावधान है। साथ ही, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने की पहल भी की जा रही है। हालांकि, कुछ किसान संगठनों को इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मजबूत होने और पारंपरिक अधिकार प्रभावित होने की आशंका है।

बीज अधिनियम 1966 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण की मौजूदा व्यवस्था को कमजोर माना जा रहा है, जिसके चलते नकली और अप्रमाणिक बीजों का कारोबार फल-फूल रहा है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नई बीज किस्मों का विकास और उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 2014 से 2025-26 के बीच 3,236 से अधिक उच्च उत्पादक किस्मों को अधिसूचित कर चुका है। प्रमाणित बीजों की उपलब्धता भी वर्ष 2015-16 के 351.77 लाख क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 508.60 लाख क्विंटल से अधिक हो गई है। बीज उपलब्धता मांग से अधिक है। इसके बावजूद, कपास जैसे क्षेत्रों में अधिकतम बिक्री मूल्य तय होने के बाद भी गैर.मानक बीजों की बिक्री जारी है। वर्तमान में भारतीय बीज बाजार का लगभग 75 फीसदी हिस्सा निजी क्षेत्र के पास है, जबकि सार्वजनिक बीज कंपनियां कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे मेंए बीज क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

घटिया खाद से तबाह होती खेती

रासायनिक खादों और कृषि उत्पादन के बीच गहरा संबंध है। पौधों के विकास में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में यूरिया उत्पादन वर्ष 2020-21 में 246.05 लाख टन था, जो वर्ष 2024-25 तक 306.67 लाख टन हो गया, जबकि डीएपी उत्पादन 37.74 लाख टन के आसपास स्थिर बना रहा। नकली बीजों जैसा संकट रासायनिक खादों को लेकर भी है। वर्ष 2022-23 में 1.66 लाख छापामारियां हुई और 627 लाइसेंस निरस्त हुए। वर्ष 2025-26 में 3.51 लाख छापेमारी हुई, लेकिन समस्या यथावत कायम है।

हालात ये हैं कि गत वर्ष राजस्थान में जांच के दौरान 13 कंपनियों के विविध उर्वरकों में सक्रिय तत्वों की मात्रा शून्य तक पाई गई। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद टीम के साथ जाकर किशनगढ़ में छापा मारकर नकली यूरिया, डीएपी और पोटाश का कारखाना पकड़ाए जहां नकली खाद बन रही थी और प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम से बेची जा रही थी। बीते दशकों में खाद की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ नकली खाद की समस्या भी बढ़ती रही है। कालाबाजारी करने वाले लोग सस्ती खाद को महंगी और गुणवत्ता वाली खाद की बोरी में भरकर बेचते रहे हैं। नकली खाद की दूसरी श्रेणी के उर्वरक तो बिल्कुल नकली होते हैं, जहां यूरिया में साधारण नमक, डीएपी में दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में बालू, राख व जिप्सम की गोलियां, एमओपी में बालू, साधारण नमक और ईंट का चूर्ण एवं कॉपर सल्फेट की मिलावट होती है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद ने उर्वरकों की मिलावट के लिए त्वरित जांच की कुछ विधियां विकसित की हैं, जो घर पर भी आसानी से अमल में लाई जा सकती हैं, अधिकतर किसानों को इसकी खास जानकारी नहीं है।

उर्वरक सब्सिडी वर्ष 2025-26 में 1,86,460 करोड़ रुपये से घटकर 2026-27 में 1,70,781 करोड़ रुपये रह गई। उर्वरकों व इसके कच्चे माल की कमी आयात से पूरी की जाती है। वर्ष 2015 से स्वदेशी और आयातित यूरिया नीम लेपित की जा रही है। वर्ष 2017 में यूरिया की 50 किग्रा की बोरी के स्थान पर 45 किग्रा की बोरी आरंभ कर खपत 10% कम करने की परिकल्पना की गई। वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ कर 25.61 करोड़ कार्ड बांटे गए हैं, पर खादों का असंतुलित प्रयोग जारी है। वर्ष 2023 में पीएम प्रणाम योजना भी बनी, मगर खादों का उपयोग सीमित नहीं हो सका है। नकली खाद के कुचक्र ने समस्या को बढ़ा दिया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। नैनो यूरिया और डीएपी जैसे इफ्को के नवाचार सामने आए हैं, पर किसानों का भरोसा अब भी पारंपरिक खादों पर है और नैनो यूरिया को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

मिलावटखोरों की चांदी

कीटनाशकों में भी जोर.शोर से मिलावट हो रही है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान देश भर में 2,42,095 नमूनों के विश्लेषण में 6,540 नमूने गलत ब्रांड के थे। देश में लगातार बढ़ रही कीट व्याधियों के कारण कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। अभी भी काफी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग कपास पर हो रहा है। कई कीटों में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। इस कारण कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाने के लिए किसान विवश हैं।

समाधान का रास्ता

किसानों की इन समस्याओं पर नौकरशाही खास चिंतित नहीं दिखाई देती है, क्योंकि खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इसलिएए नीति निर्माता यथास्थिति से संतुष्ट हैं। वर्ष 2013-14 में 265 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 357.7 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसी अवधि में बागवानी उत्पादन 277.4 मिलियन टन से बढ़कर 369.1 मिलियन टन हो गया। लेकिन, किसानों को चिंता हैए क्योंकि वे न केवल खाद, बीज और कीटनाशक बल्कि बहुत से कृषि आदान और डीजल-पेट्रोल तक मिलावटी खरीद रहे हैं। अगर कहीं संगठित रूप से किसान प्रमाण के साथ लड़ते हैं, तो कुछ लाइसेंस निरस्त हो जाते हैं। मगर, ये देखा गया है कि काले धंधों में लगे लोग दूसरी कंपनी बनाकर दूसरे नाम से उत्पाद बनाने लगते हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इन मसलों पर खास ध्यान रहा है। उनका कहना है कि घटिया या नकली दवाई, खाद और बीज के मामलों में हम किसानों को लुटते हुए नहीं देख सकते। लेकिनए मौजूदा स्थिति केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से ही सुधर सकती है। गड़बड़ी करने वालों के मन में कमजोर कानूनों के कारण कोई भय नहीं है। इसलिए, घटिया कीटनाशकों और बीजों पर कठोर दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने की जरूरत है। हाल में कृषि और डाक विभाग में कृषि बीज, खाद और कीटनाशक के सैंपलों की सुरक्षित, टैंपर. प्रुफ एवं डिजिटल ट्रैकिंग आधारित ढुलाई को लेकर समझौता हुआ है। इससे प्रयोगशालाओं से समय पर विश्वसनीय रिपोर्ट मिल सकेगी और मिलावटखोरों के खिलाफकठोर कार्रवाई संभव होगी।

इससे नकली कृषि सामग्री के प्रचलन को रोकने में मदद मिलेगी।यह उचित समय है कि सरकार कृषि इनपुट की बिक्री के मामले में कुछ नई व्यवस्थाएं भी करे। जैसे दवा विक्रेताओं के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता हैए वैसा ही प्रावधान कृषि इनपुट्स की बिक्री के मामले में करने पर विचार किया जाना चाहिए। बेशक जो लोग इस कारोबार में हैं, इसका विरोध करेंगे। परए यह काम प्रायोगिक आधार पर करके अनुभव लिया जा सकता है। साथ ही, इस मुद्दे पर कृषि विज्ञान केंद्रों को और अहम भूमिका में लाने की जरूरत है ताकि किसानों को साल दर साल लुटने से बचाया जा सके।

खाद.बीज एवं कीटनाशक दवाई का ले पक्का बिल

इन दिनों खासकर गांवों मे कुछ लोग नकली खाद-बीज से लेकर फसलों के लिए कीटनाशक दवा आदि संबंधित रसायन बेच रहे है। इनसे बचे। वैसे कृषि विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए इनका पता लगाने का प्रयास करता है, लेकिन कम कीमत की लालच में कई किसान ऐसे दवाई, खाद- बीज विक्रेताओं के झांसे में आ जाते है। किसान भी इनसे सावधान रहे और ि लाइसेंस धारी दुकानदार से ही खाद-बीज, दवाईयां आदि ले। कृषि आदान खरीदी के दौरान पक्का बिल जरुर ले। अन्य लोगों से बीज आदि खरीदने से बचे। अनाधिकृत रुप से बैचने वालों का खाद- बीज नकली ही होगा या फिर काफी घटिया होगा। जिससे किसानों को कम पैदावार रुप में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वैज्ञानिकों ने चेताया 2030 तक 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान

नई दिल्ली। धरती लगातार और ज्यादा गर्म होती जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र ने एक नई चेतावनी देकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले पांच सालों तक दुनिया का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि धरती का तापमान उस खतरनाक सीमा को पार कर जाए, जिसे रोकने की कोशिश कई सालों से की जा रही है। आर्कटिक इलाके तेजी से गर्म हो रहे हैं, मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है और कई जगहों पर भारी बारिश तो कई जगह सूखे का खतरा बढ़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने 28 मई को चेतावनी जारी की है कि इस साल और इसके बाद आने वाले अगले चार सालों तक दुनिया का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या उसके करीब बना रह सकता है। अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म 11 साल साल 2015 के बाद आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मौसम और जलवायु एजेंसी ने कहा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और साल 2031 से पहले एक नया सबसे गर्म साल आने की संभावना है। यानी ऐसी गर्मी होगी जो हमने आजतक नहीं देखी होग।

अगले पांच सालों में दुनिया का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या उसके बेहद करीब रहने की संभावना है..

86 प्रतिशत संभावना है कि 2026 से 2030 के बीच कोई एक साल 2024 को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सबसे गर्म साल बन जाएगा।

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि 2026 से 2030 के बीच पांच साल का औसत तापमान 1850-1900 के औद्योगिक दौर से पहले के औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने की 75 प्रतिशत संभावना है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब मई में ही भारत झुलस रहा है। इस समय पश्चिमी यूरोप बहुत गर्म मौसम की चपेट में है। ब्रिटेन और फ्रांस में मई महीने के तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं।

2027 पर अल नीनो का असर

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ग्लोबल एनुअल.टू.डेकैडल अपडेट रिपोर्ट के मुख्य लेखक लियोन हरमैनसन ने कहा 2026 के आखिर में अल नीनो आने की संभावना है। इससे 2027 में सबसे गर्म साल बनने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले अल नीनो का असर यह रहा कि 2023 दुनिया का दूसरा सबसे गर्म साल बना। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। उस समय तापमान औद्योगिक दौर से पहले के औसत से लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था।

अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का सतही तापमान बढ़ जाता है। इससे दुनिया भर में हवाओं, वायुदाब और बारिश के पैटर्न में बदलाव आता है। यह आमतौर पर हर दो से सात साल में होता है और करीब 9 से 12 महीने तक रहता है।

1.3 डिग्री से 1.9 डिग्री तक का खतरा

साल 2015 के पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य था कि धरती का तापमान औद्योगिक दौर से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखा जाए और कोशिश हो कि यह 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। इन लक्ष्यों की गणना 1850-1900 के औसत तापमान के आधार पर की जाती है। यही वह समय था जब इंसानों ने बड़े पैमाने पर कोयला, तेल और गैस जलाना शुरू नहीं किया था। इनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। लेकिन अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि 2026 से 2030 के बीच दुनिया का औसत सतही तापमान 1850-1900 के औसत से 1.3 डिग्री से 1.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का अनुमान है। संगठन ने कहा कि 91 प्रतिशत संभावना है कि 2026 से 2030 के बीच कम से कम एक साल ऐसा होगा, जब दुनिया का औसत तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर जाएगा। इसके अलावा 75 प्रतिशत संभावना है कि पूरे 2026.2030 के पांच साल का औसत तापमान भी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा।

हम जिस दुनिया को जानते थे वो पहले जैसी नहीं रही। धरती लगातार तप रही है। हर गुजरते साल के साथ गर्मी के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं। मौसम पहले से कहीं ज्यादा बेरहम होता जा रहा है। धरती लगातार तप रही है और आने वाले पांच साल इस संकट को और भयावह बना सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और ब्रिटेन के मौसम विभाग की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2026 से 2030 के बीच वैश्विक तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगले पांच वर्षों में गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं और 86 फीसदी आशंका है कि इस दौरान कोई एक साल इतिहास का सबसे गर्म साल बनेगा।

रिपोर्ट के अनुसार 91 फीसदी आशंका है कि इन वर्षों में कम से कम एक बार तापमान अस्थाई रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर जाएगा।

वैज्ञानिकों ने यह भी चेताया है कि आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में साढ़े तीन गुना तेजी से गर्म हो रहा हैए जिससे समुद्री बर्फ तेजी से पिघलेगी। वहीं मौसम का मिजाज भी पूरी तरह बदल सकता है।

कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ेगा तो कहीं सूखे की मार गहराएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह केवल बढ़ते तापमान की कहानी नहीं, बल्कि हमारी खेती, पानी, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर मंडराता गंभीर संकट है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिननं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 9826225025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)